गणतंत्र दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
डॉ. धनंजय सिंह
विपणन निरीक्षक अधिकारी
श्रीदत्तगंज जनपद
बलरामपुर

गणतंत्र दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
डॉ अश्विनी कुमार गौतम

पशु चिकित्सा
अधिकारी श्रीदत्तगंज
बलरामपुर

गणतंत्र दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
आज्ञाराम यादव
प्रधान

ग्राम पंचायत गालिबपुर
विकासखंड श्रीदत्तगंज
जनपद बलरामपुर

गणतंत्र दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ रविंद्र
कुमार यादव
वरिष्ठ नेत्र परीक्षण
अधिकारी सामुदायिक
स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज
बलरामपुर

गणतंत्र दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
सुजीत कुमार पाण्डेय
चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक
स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज
बलरामपुर

गणतंत्र दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
शशि प्रताप सिंह
चौकी प्रभारी
श्रीदत्तगंज जनपद
बलरामपुर

गणतंत्र दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
विश्व मोहन श्रीवास्तव
प्रधानाध्यापक
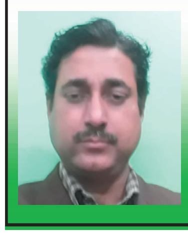
उच्च प्राथमिक विद्यालय
वाय भीड श्रीदत्तगंज
जनपद ,बलरामपुर

गणतंत्र दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

जगदीश
वर्मा
प्रधान
ग्राम बरगदवा
ब्लॉक श्रीदत्तगंज
जनपद बलरामपुर

बजट 2021 : बालिका शिक्षा पर बढ़ता खतरा

सरकार को जेंडर सेंसिबल पॉलिसी लाने की जरूरत

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। देखने लायक होगा कि इस बार बजट में शिक्षा के लिए सरकार कितनी धनराशि आवंटित करती है। देश में 10 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर स्कूल खोले जाने की घोषणाएं हो रही हैं। कोरोना महामारी के चलते देश के 15 लाख स्कूल मार्च 2020 से ही बंद हैं। लगभग 30 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इस कठिन समय में स्कूलों के खोले जाने और बच्चों की स्कूल में वापसी के लिए आवश्यक धनराशि का बेहद जरूरी कदम होगा।

वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत नागरिक सामाजिक संगठनों (सिविल सोसायटी ऑर्गनाइजेशंस) के साथ 17 दिसंबर, 2020 को बजट पूर्व विचार-विमर्श (प्री-बजट कंसल्टेशन) आयोजित किया था। जिसमें राइट टू एजुकेशन (आरटीई) फोरम सहित कई संगठनों ने शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च को बढ़ाकर ऋद्ध के 6% तक किए जाने की मांग उठाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में किए गए वायदे के अनुसार ह्यजेंडर एंड इंक्लूसिव फंडह्न गठित करने के लिए अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराने पर जोर दिया। ताकि लड़कियों की शिक्षा के समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटा जा सके।

शिक्षा अधिकार कानून लागू होने के बाद लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई

कोरोना महामारी ने पहले से ही देश की शिक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। अब जब 10 महीने के बाद स्कूल खुलने की बात हो रही है तो 20 से 25 प्रतिशत बच्चों के ड्रॉप

आउट हो जाने की आशंका जताई जा रही है। इनमें अधिकांशत: लड़कियां और दलित, आदिवासी, विकलांग एवं गरीब-वंचित परिवारों के बच्चों की संख्या शामिल है। शिक्षा अधिकार कानून, 2009 के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में बच्चों ने स्कूलों में दाखिला लिया था। जिनमें लड़कियों की संख्या में वृद्धि उल्लेखनीय थी। हालांकि, कमजोर आधारभूत संरचना और माध्यमिक स्कूलों की उपलब्धता में कमी के चलते लड़कियों के प्रारम्भिक (एलीमेंटरी) से माध्यमिक (सेकेंडरी) वर्गों में जाने की संभावनाएं कमजोर हो जाती हैं।

प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के बाद पढ़ाई जारी रखने में लड़कियां असमर्थ

बाल संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 15 से 18 आयु वर्ग की 40% लड़कियां प्रारंभिक स्तर की स्कूली शिक्षा के बाद अपनी शिक्षा जारी रख पाने में असमर्थ हैं। यह आंकड़ा लड़कियों की 12वीं तक की शिक्षा पूरी करने के मामले में काफी चुनौतीपूर्ण है। यह दशार्ता है कि माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने तथा पूर्णकालिक, नियमित, प्रशिक्षित व योग्य अध्यापकों की तत्काल नियुक्ति किए जाने की जरूरत है।

पिछले साल सितंबर के महीने में एक लिखित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री श्री पोखरियाल ने खुद स्वीकार किया था कि देश के स्कूलों में 17.1 फीसदी शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन्हें तत्काल भरे जाने की जरूरत है। शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए योग्य अध्यापकों का होना जरूरी है। इसलिए संविदा (कांट्रैक्ट) पर रखे जाने वाले अप्रशिक्षित व कम मानदेय वाले अध्यापकों की नियुक्ति से बचना होगा।

ऑनलाइन शिक्षा ने गांव के छात्रों की मुश्किलें बढ़ाई

यू डाइस 2016-17 के एक आंकड़े के मुताबिक 18% अध्यापक योग्यता के मामले में शिक्षा अधिकार कानून, 2009 के मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। इन्हें प्रशिक्षित और नियमित करने का काम भी अभी किया जाना है। ऑनलाइन शिक्षा के कारण भी असमानता की एक बड़ी खाई पैदा हो गई है, क्योंकि 80 प्रतिशत गांवों में रहने वाले तथा शहरों के गरीब बच्चे, जिनमें लड़कियों की संख्या बहुतायत है, कम्प्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट फोन और उचित संसाधनों के अभाव के कारण शिक्षा के दायरे से बाहर होते जा रहे हैं।

शिक्षा अधिकार कानून अभी 12.7% स्कूलों में ही लागू हो पाया

शिक्षा अधिकार कानून 2009 को 11 साल गुजर जाने के बाद भी पूरी तरह अमल में नहीं लाया जा सका। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यह महज 12.7% स्कूलों में ही लागू किया जा सका है। अभी भी हमारे 52% स्कूल आधारभूत संरचना की कमी से जूझ रहे हैं। जहां स्वच्छ पीने का पानी, हाथ धोने की सुविधा व प्रयोग में लाने लायक शौचालय नहीं है। आर्थिक संसाधनों के बगैर न तो शिक्षा अधिकार कानून पूरी तरह लागू हो सकता है और न ही हाल में कैबिनेट द्वारा स्वीकार की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हो सकता है।

1966 में भारत के पहले शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) ने शिक्षा पर देश की ऋद्ध का 6% खर्च करने के लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर सके। शिक्षा का आवंटन हमेशा 3-4% के बीच बना रहा।

केंद्र एवं राज्य दोनों को ही शिक्षा पर धनराशि खर्च करनी होती है जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। इसमें गरीब एवं पिछड़े राज्य, खासकर उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के राज्य धनराशि के आवंटन के मामले में काफी पीछे रह जाते हैं। जिससे शिक्षा में असमानता की बड़ी खाई खड़ी हो जाती है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का 60% केवल विज्ञापन पर खर्च हो गया

पिछले दिनों लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ह्लबेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओह्न के अंतर्गत एक योजना की शुरूआत की थी. मगर उसका गम्भीरता से पालन नहीं हो सका। 2018-19 में इसके लिए निर्धारित धनराशि का 60% केवल विज्ञापन पर ही खर्च कर दिया गया।

इस तरह की योजनाओं के लिए धन आवंटित करने के साथ ही स्पष्ट कार्ययोजना की जरूरत है, ताकि धनराशि को सही जगह खर्च कर उत्साहवर्धक परिणाम हासिल किए जा सकें। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्यान्ह भोजन योजना को विस्तारित करते हुए सुबह का नाश्ता देने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी।

किसानों के लिए कृषि मंत्री ने किया सीड ट्रेसबिलिटी मोबाइल एप लांच

*गुण नियंत्रण एवं डीएनए प्रयोगशाला का भी शुभारंभ व लाभांश रु0 9.00 करोड़ का वितरण *बीज के क्षेत्र में काम करने वालों की अहम जवाबदारी-श्री तोमर राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ने लाभांश स्वरूप लगभग नौ करोड़ रूपये भारत सरकार को प्रदान किये

नई दिल्ली। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा लाभांश वितरण के अवसर पर सीड ट्रेसबिलिटी मोबाइल एप लांच किया। इस एप के माध्यम से असली बीजों की जानकारी मिलेगी और किसान धोखाधड़ी से बच सकेंगे। कार्यक्रम में श्री तोमर ने गुण नियंत्रण एवं डीएनए प्रयोगषाला का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर उन्होनें कहा कि खेती के क्षेत्र में बीज की बड़ी महत्ता है, ऐसे में बीज के क्षेत्र में काम करने वालों की बहुत अहम जवाबदारी होती है।

पूसा स्थित राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के मुख्यालय में आयोजित समारोह में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक विनोद कुमार गौड़ ने भारत सरकार के लिए लगभग नौ करोड़ रूपये के लाभांष का चेक श्री तोमर को सौंपा। कार्यक्रम में श्री तोमर ने श्री शंकरन द्वारा संपादित पुस्तक एनएससीज जर्नी इन द सर्विस आफ फार्मर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसमें एनएससी की

स्थापना से लेकर अब तक की प्रमुख उपलब्ध्यिों को संजोया है। श्री तोमर ने कहा कि व्यक्ति हो या संस्था, दोनों के सफर के स्मरण को संजोना बहुत ही सुखद होता है। श्री तोमर ने कहा कि एनएससी के पास भूमि का काफी बड़ा रकबा है, जिसका अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। उपलब्ध योजनाओं के माध्यम से सफलता प्राप्त कर आगे बढ़ सकते है। एनएससी कम दाम पर गुणवत्ता बीज किसानों को उपलब्ध करा रहा है, यह देष के लिए बड़ा काम है, जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में प्रगति के लिए एक रोडमैप बनाने का सुझाव दिया। श्री तोमर ने कहा कि सीड ट्रेसबिलिटी मोबाइल एप मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने कहा कि कृशि की शुरूआत बीज से होती है। वैरायटी सीड्स की ज्यादा मात्रा में किसानों को उपलब्धता सस्ते दामों में सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने एनएससी के फार्मों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने का सुझाव दिया।

कृषि राज्य कैलाश चौधरी ने कहा कि खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता में किसानों व वैज्ञानिकों के साथ ही एनएससी का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि नई लैब व एप से किसानों का काफी लाभ होगा। प्रारंभ में सीएमडी ने एनएससी की गतिविधियां व उपलब्धियां बताई। एनएससी ने विभिन्न कदम उठाकर दुर्गम व दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों को अनाजों, दलहन-तिलहन, चारा, सब्जी बीज आदि की सभी महत्वपूर्ण फसलों के गुणवत्ता बीजों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाने के सरकार के उद्देश्य को पूरा किया है व गुणवत्तापूर्ण बीजों के भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को कायम किया है। वर्ष 2019-20 में एनएससी की कुल आय 1085.44 करोड़ रु0 रही है एवं कर पूर्व लाभ रु0 60.88 करोड़ रहा है।

दिल्ली हिंसा के सबूत जुटाने लाल किला पहुंची फॉरेंसिक टीम

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान भड़की हिंसा के सिलसिले में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम सबूत जुटाने के लिए शनिवार को लाल किला पहुंची।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की पहचान करने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। पुलिस ने लाल किला परिसर में तोड़फोड़ किए जाने की घटना को राष्ट्र विरोधी गतिविधि बताया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने लाल किले का दौरा किया और यह साक्ष्य एकत्र कर रही है। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की साजिश और आपराधिक मंसूबों की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि किसान नेताओं के साथ बनी सहमति को दरकिनार करने की पूर्व नियोजित तथा सोची-समझी योजना थी ताकि गणतंत्र दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को शर्मिंदा कराया जा सके। पुलिस ने कहा कि आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की राजद्रोह से संबंधित धाराओं के तहत जांच की जा रही है। इसके साथ ही भारत तथा देश से बाहर स्थित लोगों और संगठनों की भूमिका तथा गतिविधियों की जांच की जा रही है।गौरतलब है कि 26 जनवरी को किसान संगठनों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी निर्धारित मार्ग से अलग हो गए थे।प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किला परिसर पहुंच गए थे, जबकि उनमें से कुछ ने इस ऐतिहासिक स्मारक के गुंबदों और उस प्राचीर पर धार्मिक झंडा लगा दिया था।

टीएमसी के कई नेता विजयवर्गीय के साथ दिल्ली पहुंचे

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल यात्रा रद्द होने के बाद शनिवार दोपहर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस (ळटउ) के बागी नेताओं को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली भेज दिया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को इजरायली दूतावास के नजदीक हुए आईईडी ब्लास्ट के बाद अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरा रद्द कर दिया। शनिवार दोपहर 4.10 मिनट पर कोलकाता से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वालों में बंगाल के पूर्व मंत्री राजीब बनर्जी भी शामिल थे।

इसके अलावा हावड़ा के डोमजूर विधानसभा सीट से विधायक राजीब बनर्जी ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। साथ में हवाड़ा के बल्ली से विधायक वैशाली डालमिया जिन्हें हाल ही में टीएमसी ने पार्टी से बाहर कर दिया था, हुगली जिले के उत्तरपारा से विधायक प्रबीण घोषाल, हावड़ा शहर के पूर्व मेयर राथिन चक्रवर्ती, राणाघाट से पूर्व विधायक पार्थ सारथी चटर्जी और अभिनेता रुद्रनील घोष शामिल हैं। घोष हाल ही में टीएमएसी के खिलाफ बोलना शुरू किया था।

दि सेकसरिया बिसवां शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, बिसवां, सीतापुर
(आई0एसओ0) 9001:2015, 14001:2015 एवं 22000:2018 द्वारा प्रमाणित)
समस्त क्षेत्रवासियों, कर्मचारियों एवं किसान भाईयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
सफेद दानेदार उच्च कोटि की चीनी, एथनॉल, 32 मेगावाट विद्युत का सह उत्पादन एवं जैव समृद्ध जैविक खाद के निर्माता
गन्ना आपूर्ति में पारदर्शिता लाने हेतु दी जाने वाली सुविधाएं-
ई-गन्ना प्रणाली के अन्तर्गत ई-गन्ना ऐप के साथ साथ टोल फ्री नम्बर से जानकारी प्राप्त करने की सुविधा :-
(क) कार्यालय, गन्ना एवं चीनी आयुक्त - 1800-121-3203,
(ख) गन्ना पर्ची सम्बन्धी जानकारी - 1800-103-5823,
(ग) खेती से सम्बन्धित जानकारी - 1800-180-1551
कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु हैण्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साबुन से बार-बार हाथ धोयें, सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखें। को/कोविशिल्ड वैक्सीन का इंतजार करें।
कोरोना को हराना है,
देश को बचाना है।
मृदा परीक्षण अवश्य करायें संस्तुति के आधार पर उर्वरक लगायें
*ट्रेन्च विधि से गन्ने की बुवाई करायें, सह फसल के साथ दोहरा लाभ कमायें।
*पराली एवं गन्ने की पत्ती न जलायें, ट्रैश मल्चर से जुताई कर जैविक खाद बनायें।
* गन्ना प्रजाति को.पी.के. 05191 की बुवाई कदापि न करें। उन्नति शील प्रजाति को.लख. 94184 को 98014 को. शा.08272 एवं को.0118 व को. 0238 को. अपनायें।
रमेश चन्द्र सिंघल
मुख्य अधिशासी

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के पावन पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों व देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं
कार्यालय : मुख्य चिकित्साधिकारी श्रावस्ती
शिशु सुरक्षायोजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली नि:शुल्क सुविधाए
अपील
सभी गर्भवती माताये, आशा बहू के माध्यम से अथवा महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री से अपना पंजीकरण अवश्य कराये।
* टी0टी0के टीके लगवाये तथा खाने के लिए आयरन फोलिक ऐसिड की गोलिया अवश्य प्राप्त करे।
* हीमोग्लोबिन तथा ब्लड प्रेशर अवश्य जॉच कराये, साथ ही समय समय पर प्रसव पूर्व जॉच कराकर चिकित्सक / स्वास्थ्य कार्यकत्री से उचित सलाह प्राप्त करे।
* प्रसव निकटतम सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर ही कराये इसके लिए प्रत्येक गॉव मे कार्यरत आशा बहू से सहयोग प्राप्त करे।,
* प्रसव के तुरन्त बाद नवजात शिशु का स्तनपान जरूर कराये।
* सभी गर्भवती महिलाओ को चिन्हित स्वास्थ्य केन्द्रो / उपकेन्द्रो पर 102 एम्बुलेस वाहन से नि:शुल्क आवागमन की सुविधा, भोजन, दवा तथा अन्य जॉच की सुविधा उपलब्ध है एवं उनके खाते मे बैक पासबुक की छायाप्रति जमा करने पर 1400/00स्थानान्तरण की सुविधा है।

डा0ए0पी0भार्गव
मुख्य चिकित्साधिकारी
श्रावस्ती
टी0के0शिबु
जिलाधिकारी
श्रावस्ती